[श्री वेणीशंकर शर्मा]

गया था तब वहां सुना था कि केन्द्र की होम मिनिस्ट्री से एक ऐसा आदेश गया है जिसके अनुसार पांच वर्ष या उससे अधिक से जो पाकिस्तानी घुसपैठिये असम में बसे हुए हैं। उन्हें यहां की नागरिकता प्रदान कर दी जाय। तस्वीर साफ है कि जहां हम हिन्दुओं की संख्या को कम करना चाहते हैं वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और इस में किस का स्वार्थ हो सकता है यह आपके सामने है। मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो कमीशन बिठलाया है उस के साथ साथ उस को अपनी इंटेलीजेंस के द्वारा भी तहकीकात करने के लिए उचित कदम उठाने चाहियें।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address which has been moved. By and large, in this year's President's Address, all the major problems facing the nation have been put forward for the consideration of this nation and of this House. I would like to make a few observations regarding the policy towards Pakistan, China and on the language problem. This year also, in the President's Address, the hope has been expressed for better and friendly relations with Pakistan and this hope has been placed on the Tashkent declaration. I would like to draw your attention to the President's Address of 1966, where it is stated:

> "It was Shri Lal Bahadur Shastri's hope and belief that the Tashkent declaration would lay the foundation for an enduring peace and frindship between India and Pakistan. More even than the letter it is the spirit of the Tashkent declaration that is important."

Then, Sir, we come to the Address of 1967, and about what happened in that year, I will come a little later. There it is stated:

> "Government most sincerely desire the friendship and cooperation of the Government and people of Pakistan. Nothing has distressed it more than the bitterness and conflict which have sometimes divided the two countries which have many common interests. Government will make every effort to achieve relationship of fullest understanding and good-will and amity with Pakistan."

Then, Sir, this year it has been stated like this. I will quote one of two sentences. It is stated:

> "It is a matter of regret that our relations with Pakistan and China remain unsatisfactory."

15.59 hrs.

RE. AWARD OF KUTCH TRIBUNAL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने के साथ-साथ एक स्थगन प्रस्ताव भी पेश करना है। अभी माननीय सदस्य पाकिस्तान और भारत के रिश्ते की बात कर रहे थे। अभी-अभी मुझे खबर मिली है कि कच्छ ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है और कच्छ का 10 प्रतिशत हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में चला गया है अवार्ड के अनुसार। अभी-अभी रेडियो पर यह बात आई है। यह बड़ा गम्भीर मामला है और मेरी राय में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस चल रही है उस को अब तत्काल स्थगित कर देना चाहिये और इस मामले को ले लिया जाये। उसका कारण यह है—आप शायद उस वक्त नहीं थे लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं—कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ का करार किया था तब उन्होंने इस सदन के सामने वादा किया था कि जमीन पर केवल सीमा का अंकन करने के बारे में हम समझौता कर रहे हैं। टु डिमार्केट दि

बार्ड आर्गदि ग्राउंड । लेकिन जब करार हुआ है और उस में सीमा निर्धारित करने की बात यानी **टु डिटरमिन दि बार्डर** की बात आई थी तो उसी समय हम लोगों ने उन्हें सूचित किया था कि उस के कारण हम अपनी भूमि को खोयेंगे, और वही बात आज हो गई है ।

इस लिये मेरी आप से नम्र प्रार्थना है और संसद् कार्य मंत्री भी यहां बैठे हैं, वह भी ध्यान दें, कि यह इतना अहम और महत्व का सवाल है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चलना बेकार और बेमतलब है । इस लिये संसद् कार्य मंत्री या तो खुद इस मामले में प्रस्ताव लायें या वह मेरे प्रस्ताव को मान लें ।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : सभापति महोदय, इस के पहले कि मंत्री जी कुछ बोलें मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो गुजरात से आते हैं उन के पास कच्छ के मामले में कोई अधिकृत सूचना नहीं है । श्री मधु लिमये केवल अनुमान से कह रहे हैं । इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि यह इतना गम्भीर सवाल है कि इस के बारे में पूरी बात सदन के सामने आनी चाहिये । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सदन के सम्मुख एश्योरेंस दिया था । हमारे पास जो मा हिती है उस के अनुसार बार्डर पर पाकिस्तानी सेना तैयार है जिस में कि अवार्ड आने के बाद तुरन्त ही वहां घुस जाये । इस के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिये और कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिये । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में हाउस को विश्वास में ले कर बतलाया जाना चाहिये कि क्या स्थिति है और क्या अवार्ड आया है क्योंकि इस के बारे में हमें भी अपनी राय देनी होगी ।

सभापति महोदय : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । इस लिये ज्यों ही श्री मधु लिमये ने इस प्रश्न को उठाया मैंने संसद् कार्य मंत्री से कहा और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस मामले में सदन को जल्दी ही समय देगी ताकि इस पर बहस की जा सके क्योंकि यह सारे देश के लिए महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है । मैं चाहता हूं कि इस के संबंध में प्रधान मंत्री आकर बतलायें ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है । जब तक कोरम नहीं होगा तब तक सदन की कार्रवाई कैसे चल सकती है ?

MR. CHAIRMAN: The bell is being rung. Now there is quorum.

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : सभापति महोदय, जैसा आप ने कहा, इस प्रश्न की गम्भीरता से कोई इन्कार नहीं कर सकता । लेकिन आज जेनेवा के समय के अनुसार 4 बजे वहां जजमेंट होने वाला है । जजमेंट यहां के समय के अनुसार शायद साढ़े आठ बजे के करीब आयेगा । ऐसी स्थिति में उस के मालूम होने के पश्चात् ही कोई चीज बतलाई जा सकती है ।

श्री मधु लिमये : मालूम हो चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह : विधिवत रूप में इस की जानकारी हमें नहीं है ।

श्री मधु लिमये : विधिवत जानकारी नहीं होगी और हिन्दुस्तान चला जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : इस लिये यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये जिस के बारे में मालूम न हो । जेनेवा के समय के अनुसार जजमेंट 4 बजे होने वाला है ।

सभापति महोदय : 10 बजे प्रात: फैसला आने वाला था ।

श्री मधु लिमये : आपकी जानकारी में मैं ने बात ला दी है । अब आप को इस का फैसला करना है कि कार्रवाई स्थगित करनी है या नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : हम लोग कार्रवाई स्थगित नहीं करेंगे लेकिन हिन्दुस्तान की इंटेग्रिटी को बचाने के लिये जो भी आवश्यक कदम होंगे वह अवश्य उठाये जायेंगे ।

श्री मधु लिमये : पाकिस्तान को कच्छ मे जबरदस्ती घुसने न दो ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): सभापति महोदय, मझे एक निवेदन करना है । भारत सकार जानती है और सारे देश को पता लग गया है कि कच्छ न्यायाधिकरण ने कच्छ के पूरे भू भाग पर हमारी सर्व प्रभुता को स्वीकार नहीं किया है और एक बड़े भारी भाग को पाकिस्तान को देने का फैसला वह कर चुका है । मुझे सरकार से एक स्पष्ट आश्वासन चाहिये कि जब तक इस सदन में कच्छ के ट्रिब्यूनल के फैसले पर निर्णय नहीं हो जाता, और देश के जनमत को जान कर जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक जो हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा है उस को पाकिस्तान को बलपूर्वक हस्तगत नहीं करने दिया जायेगा ? इस बात की पूरी आशंका है कि कच्छ ट्रिब्यूनल का फैसला प्राप्त होते ही जो हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा रहा है उस पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान बढ़े । पाकिस्तान उस क्षेत्र में अपनी सेनाओं को केन्द्रित कर रहा है । मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट शब्दों में इस सदन को विश्वास दिलाये कि हम पाकिस्तान को बलपूर्वक किसी क्षेत्र को हथियाने नहीं देंगे, उसके बल प्रयोग के आगे झुकेंगे नहीं और हम लोग एक इंच भूमि भी पाकिस्तान को नहीं देंगे । जो निर्णय हो उस पर इस सदन को विचार करने का मौका मिलना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : सदन मे विचार किये जाने का जहां तक सवाल है उस में कोई इन्कार नहीं हो सकता है । लेकिन हिपोथैटिकल बात के बारे में मैं कैसे कुछ कह सकता हूं ।

श्री मधु लिमये : बाद में कुछ हो नहीं सकता है । यही होता रहा है ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Vajpayee and Mr. Limaye have said that they want a specific assurance from Government that the area that is supposed to have been given to Pakistan will not be allowed to be occupied by Pakistan forcibly till the matter is discussed here and a decision is taken by this House. A categorical assurance is demanded, and I hope the Government will give it.

DR. RAM SUBHAG SINGH :Actually, unless and until we know the position, how can we give any clear-cut assurance on a hypothetical question? This much is certain that the Government is as anxious to preserve the integrity of the country as anybody else

श्री श्रीचंद गोयल (चण्डीगढ़) : सरकार तो अभी टैक्नीकल चीजों में फंसी हुई है । और यह इन में फंसी भी रहती है । लेकिन अगर वहां पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं तो उसका हमें बन्दोबन्त करना है । अपनी सैनिक शक्ति को आप पुष्ट करें और पाकिस्तान आगे बढ़े इस बात की इजाजत आप न दें और देखें कि वह जबर्दस्ती इस इलाके के अन्दर घुसने न पाए । इसको देखना सरकार का कर्तव्य है और उसको इस दिशा मे पग उठाना चाहिये पेशतर इसके कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही करे ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : इसके बारे में स्पष्ट एश्योरेंस मिलना चाहियें ।

सरकार अगर नहीं दे सकती है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिये। यह हमारी प्रभु-सत्ता का सवाल है और यह बहुत जरूरी चीज है। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। अगर यह सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिये। दूसरी सरकार बनेगी और वह इस सवाल के साथ अपने आप डील कर लेगी। देश की प्रभुसत्ता के साथ सरकार को खेलने नहीं दिया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : जितनी लाइटली माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उस में मैं उनको कह सकता हू कि हम उनकी चालों में फंसने वाले नहीं हैं। हां जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है उस में कहीं कोई कमी हम लोगों की तरफ से न आएगी।

सभापति महोदय : मैं सरकार से एक निवेदन करना काहता हूं। यहां आशंका व्यक्त की गई है और उस आशंका के बारे में एक अधिकृत ब्यान यहां आना चाहिये कि उस क्षेत्र को पाकिस्तान बलपूर्वक हथियाा ले, उस पर पाकिस्तान बलपूर्वक अधिकार कर ले और हमारे सामने एक फेट एकम्पली पेश करे तो यह स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। इस प्रकार का एक अधिकृत आश्वासन इस सदन में सरकरार की ओर से आ जाए तो मैं समझता हू कि सदन में जो भावनायें उभरी हुई हैं वे शान्त हो जायेंगी।

डा० राम सुभग सिंह : बलपूर्वक किसी क्षेत्र को पाकिस्तान हथिया न ले इसके बारे में तो हम लोग आश्वासन देने की स्थिति में हैं और यह कहने की स्थिति में हैं कि किसी भी क्षेत्र को ऐसा नहीं रखा जाएगा कि पाकिस्तान बलपूर्वक उसको लेने की स्थिति में हो। मैं बात करूंगा प्रधान मंत्री जी से इसके बारे में। वक्तव्य अगर दिया जाना है तो कल ही दिया जा सकेगा और जजमेंट को देखने के बाद ही दिया जा सकेगा।

श्री मनुभाई पटेल : अभी जो बात हो रही है वह केवल अनुमान के आधार पर ही हो रही है। चार बजे जजमेंट होने वाला था। वहां के चार बजे यहां के रात्रि के साढ़े आठ बजे होते हैं। इस वास्ते जो यहां बात कही जा रही है वह केवल अनुमान मात्र है।

श्री मधु लिमये : अनुमान नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : ये अनुमान तो एक सप्ताह से चल रहे हैं। इस बारे में सारे देश को चिन्ता है। लेकिन हम गुजरात वालों को तो सब से अधिक चिन्ता है क्योंकि वह हमारे प्रान्त का हिस्सा है। फिर भी ऐसा कोई कदम हम न उठायें जिससे किसी प्रकार की कोई घबराहट पैदा हो।

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): There is a tendency to play down this issue. We will not allow it to be played down. It is not right, it is a matter concerning the integrity of the country.

श्री मनुभाई पटेल : आप नहीं जानते हैं। वहां के चार बजे यहां के रात्रि के साढ़े आठ बजे होते हैं। इस वास्ते इस वक्त यहां केवल अनुमान के आधार पर बात हो रही है।

सभापति महोदय : सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि बलपूर्वक किसी क्षेत्र को लेने नहीं दिया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रधान मंत्री जी भी शीघ्रातिशीघ्र इस के बारे में कोई बयान दें। इसलिए अब मैं समझता हूं कि मामला को अब हम यही खत्म कर दें और मैं आशा करता हूं ....

श्री कंवर लाल गुप्त : जिम्मेवारी से कह रहे हैं न?

सभापति महोदय : जो आश्वासन दिया है वह मंत्री के नाते दिया है और गवर्नमेंट की ओर से दिया है, इसलिए उसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। उनका आश्वासन गवर्नमेंट का आश्वासन है, यह मान कर चलना होगा।